'अप्प दीपो भव'

वॉयस ऑफ बुद्धा

Postal Reg. No.-DL(ND)-11/6144/2013-15
WPP Licence No.- U(C)-101/2013-15
R.N.I. No. 68180/98

प्रकाशन तिथि- 30 अप्रैल, 2014

मूल्य : पाँच रुपये

प्रेषक : डॉ0 उदित राज (राम राज) चेयरमैन - जस्टिस पब्लिकेशंस, टी-22, अतुल ग्रोव रोड, क्लॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001, फोन : 23354841-42

Website : www.uditraj.com E-mail: dr.uditraj@gmail.com

● वर्ष : 17 ● अंक 11 ● पाक्षिक ● द्विभाषी ● 16 से 30 अप्रैल, 2014

अतीत पर ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में मत सोचो, अपने मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो

&xtre q)

अघोषित सांप्रदायिकता

डॉ. उदित राज

सांप्रदायिक राजनीति करने का दोष प्रायः भारतीय जनता पार्टी पर मढ़ा जाता है। तथाकथित प्रगतिशील लेखक, चिंतक एवं राजनीतिज्ञों ने बार-बार आरोप लगाकर एक अवधारणा बना दिया कि जैसे भाजपा सचमुच में सांप्रदायिक दल हो। आम आदमी पार्टी की नेत्री शाजिया इल्मी का बयान कि मुसलमानों को भी सांप्रदायिक होना चाहिए। इससे बहस की गुंजाईश पैदा हो गयी। ज्यादातर मुस्लिम समाज को सांप्रदायिकता के आधार पर ही वोट देने के लिए तैयार किया जाता है। न केवल तमाम मुस्लिम नेता बल्कि कुछ हिंदू धर्म के राजनीतिज्ञ वातावरण बनाते हैं कि जो भाजपा को हराए, वोट वहां दें। सन् 1952 से ही चुनावी राजनीति इस तरह से की जा रही है। चुनाव में ही समस्याओं को रखने का सही समय होता है लेकिन मुस्लिम समाज का ऐसा मिजाज बनने ही नहीं दिया गया। मुस्लिम का वोट लेने के लिए सांप्रदायिक भावना का इस्तेमाल कहीं ज्यादा होता है उत्थान करने का काम कम।

मुसलमानों के मध्य जो सक्रिय हैं, वे इस कमजोरी को समझ गए हैं। किसी भी समुदाय या जाति की सोच उसके नेता और बुद्धिजीवी बनाने और संवारने में भूमिका अदा करते हैं। वामपंथी सोते-जागते एक ही रट लगाते रहते हैं कि देश की सबसे बड़ी समस्या सांप्रदायिकता है। इसका इनको लाभ-हानि दोनों मिला। जहां पर ये भाजपा के विकल्प नहीं बन पाये वहां पर मुसलमानों का वोट नाममात्र मिला और इनका जनाधार समाप्त हो गया। उत्तर प्रदेश और बिहार में सपा, बसपा, राजद, जद-यू और कहीं पर कांग्रेस भाजपा के विकल्प रहे, वहां पर मुसलमानों ने वामपंथियों को नकारा और इनका जनाधार ही समाप्त हो गया। इसका लाभ इनको बंगाल और केरल में मिलता रहा क्योंकि वहां पर विकल्प के रूप में यही थे। क्या मुसलमानों के ये चिंतक और राजनैतिज्ञ हितैषी कहे जा सकते हैं? क्या इन्होंने विकास और भागीदारी जैसे मुद्दों से

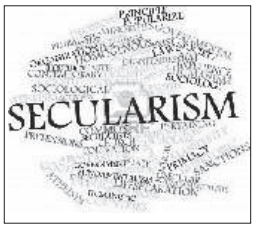

भटकाने का काम नहीं किया? मैंने स्वतः मुसलमानों के लिए बहुत कुछ करने का प्रयास किया लेकिन चुनाव में मानसिकता बन जाती है कि वोट उसको दो जो भाजपा को हरा सके। सांप्रदायिकता की अवधारणा का जितना दुरुपयोग हुआ है शायद भारतीय राजनीति में उतना और किसी का नहीं? जाति भावना से भी कहीं ज्यादा संप्रदायकिता का शोषण हुआ है।

अफसोस इस बात का है कि अब भी तथाकथित बुद्धिजीवी एवं धर्मनिरपेक्ष समझने के लिए तैयार नहीं हैं। यही कारण है कि नौजवान एवं मध्यम वर्ग इनसे दूर हटता जा रहा है। इससे प्रतिक्रिया हो रही है और भारतीय जनता पार्टी से लोग जुड़ते जा रहे हैं और इस समय कितना बड़ा कारवां बन गया है, क्या किसी से छुपा हुआ है? यही वर्ग नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री हेतु माहौल बनाने के लिए ज्यादा अग्रणीय भूमिका निभा रहा है। इनके बौद्धिक क्षमता पर भी सवाल उठता है कि जब बार-बार कहते हैं

शेष पृष्ठ 2 पर...

दोस्तों,

आपकी चाहत, नफरत, समर्थन और आपके विरोध के लिए व आपकी हर प्रतिक्रिया के लिए मेरी तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद! ऐसे ही लोकतंत्र में आप मेरे साथ रहें और मैं सामाजिक ध्येय सहित आपके बीच रहूँ, इन्हीं आशाओं के साथ एक बार फिर आप सभी चाहने वालो का धन्यवाद!

आपका
डा. उदित राज,
भाजपा उम्मीदवार,
उत्तर-पश्चिम दिल्ली लोकसभा क्षेत्र

बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर के 123वें जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

विनोद कुमार

साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात ही है कि सन् 1997 में भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा पांच आरक्षण विरोधी आदेश जारी हुए थे जिससे देश का प्रत्येक दूसरा दलित-आदिवासी कर्मचारी प्रभावित होने लगा था। वरिष्ठता, पदोन्नति में आरक्षण, खाली पदों पर भर्ती और पदोन्नति में छूट आदि अधिकार छीन लिए गए थे। इन अधिकारों को पुनः बहाल कराने के लिए सरकार के लगभग सभी विभागों ने अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ का गठन किया गया, जिसका चेयरमैन डॉ. उदित राज को बनाया गया। इन्हीं के नेतृत्व में सन् 1997,98,99 और 2000 में देशव्यापी आंदोलन हुआ और श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 81वां, 82वां एवं 85वां संवैधानिक संशोधन करके छिने अधिकारों को बहाल किया। डॉ. उदित राज ही ऐसे दलित नेता हैं जिन्होंने जातिविहीन समाज बनाने के लिए बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और बाबा साहेब डॉ. अंबेडकर के कारवां को आगे बढ़ाया, क्यों नहीं दूसरे दलित नेता ऐसा कर सके? देश के जो अन्य दलित नेता हैं उन्होंने पहले अपनी जाति को आधार बनाकर अपना वजूद स्थापित किया जबकि डॉ. उदित राज जातिविहीन और समाज जोड़ने के सिद्धांत पर चलकर दलित नेता के रूप में स्थापित हुए और इसलिए असली दलित नेता और अंबेडकरवादी कहलाने का अधिकर देश में इन्हीं का बनता है। इन्होंने निजी क्षेत्र में आरक्षण की लड़ाई की शुरुआत की और राष्ट्रीय एजेंडा बनाया, क्यों नहीं दूसरे दलित नेता ऐसा कर सके? पदोन्नति में आरक्षण का

शेष पृष्ठ 2 पर...

शेष पृष्ठ 1 का...

अघोषित सांप्रदायिकता

डॉ. उदित राज

कि आरएसएस- भारतीय जनता पार्टी फासीवादी ताकतें हैं। इन्हें इतिहास और समाज की समझ नहीं है। भारतीय समाज की तुलना और समाज से की ही नहीं जा सकती। दूसरा समाज जाति के आधार पर हजारों टुकड़ों में नहीं बंटा है। जर्मनी में यदि फासीवाद आया तो वहां का समाज एकात्म था जबकि हमारे यहां न केवल जातियों के आधार पर विभाजन है बल्कि गोत्र और गोत्रों के गोत्र और उसके आगे भी। चाहकर के भी यहां फासीवाद नहीं पनप सकता। 1977 में कांग्रेस ने तानाशाही कायम करने की कोशिश की लेकिन ऐसा संभव हो न सका। एकात्म समाज बनाने के लिए बड़े सांस्कृतिक परिवर्तन की आवश्यकता पड़ेगी जिसमें राजसत्ता का भी हस्तक्षेप जरूरी है। चीन की मिसाल दिया जा सकता है परंतु वहां की भी परिस्थितियां भिन्न थी। जापान में भी जाति व्यवस्था थी लेकिन वह समाप्त हो गयी लेकिन हमारे यहां ऐसा हो, संभव नहीं दिखता। बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर ने जातिविहीन समाज के लिए संघर्ष किया, जो पूरा हो न सका। संघ परिवार ताकतवर संगठन है अगर वह चाहे तो बात आगे बढ़ सकती है। जो लोग भाजपा और संघ परिवार को फासीवादी ताकतें होने का डर दिखाती रहती है, वे किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं है। उनमें या तो बौद्धिक क्षमता की कमी है या स्वयंस्वार्थ में ऐसा माहौल पैदा करते रहते हैं।

सन् 1990 तक कांग्रेस का लगभग एकछत्र राज उत्तर प्रदेश में हुआ करता था और उसी दौरान हिंदू और मुसलमान के झगड़े देश में ज्यादा हुए। ऐसा कोई वर्ष नहीं गुजरता था जब शहरों में कई दिनों तक कर्फ्यू नहीं लगा करता था। कांग्रेस जवाब दे कि उनके सत्ता से हट जाने के बाद अपवाद को छोड़ दिया जाए तो उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक झगड़े नहीं के बराबर क्यों हुए? गोधरा के बाद गुजरात में जो हुआ उससे कहीं बड़ा फसाद 1984 में सिक्खों के साथ हुआ। पंजाब में क्या हजारों हिंदू नहीं मारे गए थे? यहां ईमानदारी और निष्पक्षता दोनों का ही अभाव है। तथाकथित बुद्धिजीवियों एवं धर्मनिरपेक्ष नेताओं के कारण आम मुस्लिम की मानसिकता बन गयी है कि भाजपा हराओ। जो लोग ऐसा कर रहे हैं, वे भाजपा को हिंदू समाज की पार्टी मानते हैं और इसे हराने का आहावन ही सबसे बड़ी सांप्रदायिकता है। ज्यादातर मुस्लिम समाज भाजपा के खिलाफ वोट करता है और इस पर आम आदमी पार्टी का कहना कि उसे भी सांप्रदायिक होना चाहिए। उनकी समझ पर हंसी आती है कि जो उन्होंने कहा ऐसा तो मुस्लिम पहले से ही कर रहे हैं। उन्हें कहना यह चाहिए कि अब भाजपा हराओ अभियान छोड़कर के वोट उसे देने की अपील करें जो उनका विकास करे और सुरक्षा दे। इस तरह से तथाकथित ये बुद्धिजीवी और धर्मनिरपेक्ष खुद सांप्रदायिक हैं और जातिवादी भी। समाजशास्त्री आशीष नंदी ने पिछले वर्ष कहा था कि बंगाल में 100 साल में कोई दलित और पिछड़ा नेतृत्व उभर नहीं पाया। वामपंथियों का शीर्ष नेतृत्व सवर्णों के गिरफ्त में है और यही कारण है कि न केवल उत्तर भारत बल्कि अन्य स्थानों से इनकी जमीन खिसकती जा रही है। शाजिया इल्मी को बल्कि यह कहना चाहिए कि आम मुस्लिम भाजपा हराओ के बदले अपने विकास और भागीदारी के लिए वोट दें।

बुद्ध-भीम की नाव चली

बुद्ध भीम की नाव चली
दलितों को पार लगाने को।
सदियों से जो गिरे पड़े थे
उनको गले लगाने को।
ऊंच-नीच में फंसे पड़े थे
उन्हें सम्मान दिलाने को।।
बुद्ध भीम की नाव चली।।
भेदभाव का कलंक जगत में
जन-जन के भेद मिटाने को।
दुष्टों ने भी मानवता छोड़ी
उनमें मानवता लाने को।
मनु ने मारा जो उठ न सका
जन-जन को ऊपर लाने को।।
बुद्ध-भीम की नाव चली।।
थी फंसी पड़ी दलितों की नैया
भीम उदय पुंज प्रकाश हुआ।
पशु मानव में भेद नहीं था
था जाल वर्ण का रचा हुआ।
बुद्ध-भीम बन आये मसीहा
दलितों को मुक्त कराने को।।
बुद्ध-भीम की नाव चली।।
जन-जन थी डाली हथकड़ियां
था मनु ने ऐसा जाल रचाया।
अभेद-अटूट विधान बनाया
पशु मानव से पवित्र बताया।
''सुमन'' बुद्ध ने मार्ग बताया
झुकाया भीम जमाने को।।
बुद्ध-भीम की नाव चली।।

-टी. एस. सुमन

शेष पृष्ठ 1 का...

बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर के 123वें जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

अधिकार परिसंघ ने संघर्ष करके जीता था और सुश्री मायावती के मुख्यमंत्री के समय में पैरवी न करने के कारण लखनऊ हाईकोर्ट में हार हुई। बहुजन समाजवादी पार्टी जवाब दे कि क्या उसने एक भी अधिकार और सम्मान दिलाने वाला कार्य किया? सवर्णों को गाली देकर, दलितों को एकत्रित जरूर किया लेकिन क्या इससे सम्मान और भागीदारी मिल सकी? बसपा के उभार के साथ नई आर्थिक नीति देश में लागू हुई। न तो इसे रोक सके और न ही निजीकरण एवं भूमंडलीकरण के द्वारा पैदा हुए अवसरों में भागीदारी सुनिश्चित करा सके। ऐसे में इनके अस्तित्व का क्या औचित्य है?

परिसंघ के लोगों ने महसूस किया कि बाहर से संघर्ष की सीमाएं है इसलिए डॉ. उदित राज को संसद में उनकी आवाज उठाने के लिए जाना चाहिए। अब वे तैयार हो गए हैं कि देश के दलित-आदिवासी भाजपा को ताकत दें ताकि वह सरकार में आ सके और हमारी मांगें पूरी हों। 2004 में यूपीए की सरकार केंद्र में बनी लेकिन एक भी कार्य इनके हितों में नहीं हुआ। 2004 में आरक्षण कानून बनाने का विधेयक राज्यसभा में पेश हुआ लेकिन अब तक पास न हो सका। पदोन्नति में आरक्षण का भी विधेयक नहीं पास हुआ। निजी क्षेत्र में आरक्षण देने का वादा एक सपना बनकर रह गया। स्पेशल कंपानेंट प्लान एवं ट्राइबल सब प्लान को कानूनी दर्जा संसद से नहीं दे सके जबकि वादा करते रहे। इसके विपरीत एनडीए की सरकार ने तीन संवैधानिक संशोधन किए थे जो उपरोक्त में कहा जा चुका है। 26, अलीपुर रोड, दिल्ली पर बाबा साहेब का परिनिर्वाण हुआ था, भाजपा सरकार ने 2003 में उस बंगले को खरीदा और राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया। बाबा साहेब की जन्मस्थली महू को भी भाजपा सरकार ने ही विकसित किया। सन् 1990 में भाजपा समर्थित वी. पी. सिंह की सरकार ने नवबौद्धों को आरक्षण दिया। कांग्रेस दिखावा करती है लेकिन करती कुछ नहीं है। भाजपा की विचारधारा को मानने वाले सामाजिक संगठनों एवं परिसंघ के नेताओं के बीच लंबा संवाद हुआ और यह सहमति बनी कि प्रत्येक निजी क्षेत्र में भागीदारी की शुरुआत की जाएगी चाहे शिक्षा, मीडिया, उद्योग, बाजार, व्यापार, कला एवं संस्कृति आदि हों। यदि ऐसा हो सका तो भारत में एक बड़ी क्रांति होगी, इससे न केवल दलित-आदिवासी सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त होंगे बल्कि एक शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण होगा। देश की राजनैतिक बहस की दिशा सांप्रदायिकता बनाम धर्मनिरपेक्षता न होकर के हजारों वर्ष से बंटे समाज को जोड़ने की बहस होगी, वास्तव में देश में बहस का केंद्र इस मुद्दे पर होना चाहिए। हम जातियों में न बंटे होते तो क्या दूसरे हमारे ऊपर हुकूमत कर पाते?

डॉ. उदित राज का भाजपा में जाना बहुतों को आश्चर्यजनक लगा लेकिन अब लोग समझ रहे हैं और समर्थन भी दे रहे हैं और इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा को दलित-आदिवासी सर्वाधिक वोट देंगे। जो तथाकथित अंबेडकरवादी डॉ. उदित राज की आलोचना कर रहे हैं, वे इतिहास को नहीं जानते। डॉ. अंबेडकर पूरे जीवन कांग्रेस के विरोधी रहे लेकिन दबे-कुचलों की आवाज उठाने के लिए कांग्रेस के ही कोटे से संविधान सभा में चुनकर गए। कांग्रेस ने ही संविधान समिति का उन्हें चेयरमैन बनाया और मंत्री भी। इससे दलित कांग्रेस से जुड़े और उन्हें संवैधानिक अधिकार मिला। उसके बाद से कांग्रेस ने शायद ही कुछ किया और अगर किया होता तो बिना आरक्षण के भी दलित-आदिवासी विधायिका और सरकारी विभागों में भागीदारी ले पाते। अब एक नए युग की शुरुआत भाजपा के द्वारा की जाएगी और दलितों-आदिवासियों की भागीदारी प्रत्येक क्षेत्र में सुनिश्चित होगी। 2006 में उच्च शिक्षण संस्थानों में पिछड़ों को आरक्षण मिला था तो उसके विरोध में आंदोलन शुरू हुआ, पिछड़े वर्ग के सभी नेता चुप रहे और डॉ. उदित राज ही थे जिन्होंने जवाबी कार्रवायी की और आरक्षण विरोधियों को चुप कराया। लोकपाल में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों आदि को आरक्षण सुनिश्चित कराने का कार्य बहुजन लोकपाल बिल बनाकर के डॉ. उदित राज ने ही किया। सफाई के काम में ठेकेदारी प्रथा की समाप्ति और उन्हे नियमित कराने का मुद्दा लगातार उठाते रहे हैं। एक राज्य से बने जाति प्रमाण-पत्रों की मान्यता सभी राज्यों में होनी चाहिए ताकि आरक्षण सहित अन्य लाभ मिल सकें। डॉ. उदित राज ने अपने 17 वर्ष के सक्रिय जीवन को इन वर्गों के हितों के लिए आहूत कर दिया और अब संसद में जाकर के वही काम करेंगे न कि तमाम अन्य आरक्षित सांसदों की तरह वे गूंगे और बहरे बने रहेंगे। क्षेत्रीय दल नीतियां नहीं बनवा सकती इसलिए भाजपा ही हमारे पक्ष में नीति बनवा सकती है। अंत में अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परसिंघ की ओर से बाबा साहेब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर के 123वें जन्मदिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकमनाएं।

अम्बेडकर में है भारत का भविष्य

डॉ. एम. एल. परिहार

आजादी के छः दशक बाद भी हम पाते है कि देश मे एक-दूसरे के नजदीक आने की जगह एक दूसरे से दूर होते जा रहे है। आजादी के बाद यातायात व संचार माध्यमों के साधनों में क्रान्तिकारी विकास से हमारे बीच स्थानीय दूरियां तो घटी लेकिन धर्म, जाति, भाषा तथा क्षेत्रीय स्वार्थों के कारण सामाजिक दूरियां कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। आखिर ऐसा क्यों हुआ ?भारतीय समाज से जुड़े ऐसे और भी कई सवाल है जिनका उत्तर जानने के लिए यदि किसी विचारक को पढ़ने की आज सबसे अधिक जरूरत है तो वह है डॉ. भीमराव अम्बेडकर। इसका अर्थ अन्य विचारकों के महत्व को कम आंकना कतई नहीं है लेकिन निरंतर बढ़ती सामाजिक व आर्थिक, विषमता, भेदभाव व गरीब अमीर के बीच बढ़ती खाई के कारण जिस चौराहे पर हम खड़े हैं वहां से आगे जो दिशा दिखाई दे रही है वह अम्बेडकर के दर्शन की ओर जाती है। संविधान के रचयिता डॉ. अम्बेडकर ने सम्पूर्ण राष्ट्र के लिए महान योगदान दिया है लेकिन कुछ समाज सुधारक नेता व दलित वर्ग ही बाबा साहेब के जन्म दिन पर खुशियां मनाते हैं। गैर दलितों के लिए तो आज भी डा. अम्बेडकर ज्यादा मायने नहीं रखते, यह भारत का दुर्भाग्य है। लेकिन भारत का भविष्य अम्बेडकर में ही है।

डॉ. अम्बेडकर संघर्ष के प्रतीक थे। उनकी लड़ाई बाहरी लोगों से कम और अपने ही भारतीय शोषक वर्ग से अधिक थी। वे ब्रिटिश उपनिवेशवाद के स्थान पर स्थानीय जातीय वर्चस्व के उपनिवेशवाद को खत्म करना ज्यादा जरूरी मानते थे। वे एक युगद्दष्टा थे। भारतीय समाज की पुनर्रचना संबंधी उनकी परिकल्पना स्वप्नवादी चिंतकों की तरह कल्पना पर आधारित नहीं थी। वे एक व्यवहारिक व यर्थाथवादी चिंतक थे। उन्होंने एक ऐसे सामाजिक प्रारूप की रचना की जिसका आधार समता, स्वतंत्रता व बंधुत्व था। जिसमें सभी को स्वतंत्रता हो, सभी को शिक्षा एवं रोजगार के समान अवसर हो और सभी को विचार अभिव्यक्ति एवं विश्वास की पूरी आजादी हो। उन्होंने देश के राजनैतिक ढ़ांचे को लोकतांत्रिक स्वरूप प्रदान किया। उनका मानना था कि संविधान कितना ही अच्छा क्यों न हो लेकिन इसे लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होगे तो लोकतंत्र का यह मंदिर ढ़ह जायेगा। वे राजनैतिक जीवन की भांति सामाजिक व आर्थिक जीवन से भी विषमता को मिटाना चाहते थे।

डा. अम्बेडकर ने अपने जीवनकाल में राष्ट्र के सामने आई अनेक संभावित चुनौतियों एवं खतरों के प्रति आगाह किया था। उन्होंने एक राष्ट्र भाषा के सिद्धांत पर जोर दिया क्योंकि अलग-अलग भाषाओं से देश के बिखरने का खतरा था। इसी प्रकार सामाजिक व आर्थिक जीवन में विषमता को जितना जल्दी हो सके मिटाये जाने के प्रति आगाह किया था। उनका कहना था कि 26 जनवरी 1950 को हम एक ऐसे जीवन मे प्रवेश कर रहे है जिसमें राजनैतिक दृष्टि से सभी समान होंगे लेकिन सामाजिक व आर्थिक जीवन में विषमता बनी रहेगी। यदि इस

विषमता को जल्दी दूर नहीं किया गया तो इस शोषण का शिकार वर्ग उस संवैधानिक ढ़ांचे का उखाड़ फेकेंगे जिसे संविधान सभा ने कड़ी मेहनत से बनाया। उन्होंने देश के विभाजन तथा कश्मीर समस्या पैदा होने के समय धार्मिक आधार पर जनसंख्या के पूरी तरह से स्थानांतरण किये जाने पर जोर दिया था। यदि उनकी बात मान ली गई होती तो देश मे न तो आज सांप्रदायिक समस्या इतनी उग्र होती और न ही कश्मीर समस्या इतनी विकट होती। बाबा साहेब का विचार दर्शन भारत को जीवंत व प्राणवान बनाने की संजीवनी है। राष्ट्र इस संजीवनी को आत्मसात करने में जितना अधिक समय लगायेगा उतना ही पीछे रहेगा।

डॉ. अम्बेडकर का कहना था कि धर्म मनुष्य के लिए है मनुष्य धर्म के लिए नहीं। वे धर्म चाहते थे, धर्म के नाम पर पाखंड नहीं तथा उनका धर्म तर्क, विवेक, चिंतन व वैज्ञानिक सोच पर आधारित था। इसी कारण उन्होंने विवेक व विज्ञान के प्रति निष्ठा रखने वाले बौद्धधम्म को स्वीकारा। राष्ट्र व धर्म दोनों अलग-अलग है तथा धार्मिक उन्माद व खींचतान से देश के विकास के सवालों का निपटारा नहीं हो सकता। धर्म एक व्यक्तिगत विषय है। देश का विकास सामाजिक नीति से हो जिसका आधार स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व पर आधारित हो। उनका मानना था कि जिस धार्मिक व सामाजिक व्यवस्था में जात-पात, ऊंच-नीच, छूआछुत व भेदभाव के प्राण बहते हो वह धर्म नहीं एक बड़े वर्ग को गुलाम बनाये रखने का षड्यंत्र है। आजादी के 66 वर्ष बाद भी आज देश में विकास के मुद्दे गौण हैं। सामाजिक, आर्थिक विषमता की खाई दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। धर्मस्थल करोड़ों-अरबों रूपयों के केन्द्र बन गये हैं। धर्मगुरु सोने के सिंहासन पर बैठ कर सादगी के उपदेश दे रहे हैं, ऐसे में अम्बेडकर के सम्पूर्ण वैचारिक आंदोलन को समझने के बाद ही हमें इस बात का एहसास होगा कि वह इस देश के महान राष्ट्रभक्त नेता थे, हैं और रहेगें।

भारतीय समाज में ज्यादातर लोगों की यह धारणा है कि डा. अम्बेडकर ने केवल दलित वर्गों की भलाई के लिए ही अपना जीवन संघर्ष किया इसी कारण उन्हें सिर्फ दलितों के मसीहा के रूप में उभारा जाता है लेकिन यह धारणा न केवल उनकी बहुमुखी प्रतिभा को एक सीमित दायरे में बांधती है बल्कि उस महान प्रतिभा के व्यक्तित्व व कृतित्व का लाभ लेने से भी वंचित करती है। वे एक महान अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, कानूनविद, महिलाओं व मजदूरों के उद्धारक, समाज सुधारक, संविधान रचयिता व सच्चे राष्ट्रभक्त थे। देश की आजादी से पहले व बाद में देश में पैदा हुई विभिन्न ज्वलंत समस्याओं के समाधान में उनके अमूल्य योगदान की जानकारियां बहुत कम लोगों को है। उनकी तकनीकी सुझबुझ की एक बड़ी योजना थी नदी घाटी परियोजना। देश की नदियों द्वारा हर वर्ष बाढ़ से भीषण तबाही की समस्या के समाधान की वह ठोस योजना थी जिसमें दामोदर नदी पर बांध योजना, विद्युत उत्पादन, सिंचाई के पानी की व्यवस्था, जल परिवहन के प्रावधान आदि शामिल थे।

बाबा साहेब महिलाओं व मजदूरों के हितों के पक्के हिमायती थे। कानून मंत्री के रूप में इन वर्ग के कल्याण में ऐसे कई कार्य किये। कानून मंत्री के रूप में हिन्दू स्त्रियों के उद्धार हेतु हिन्दू कोड बिल पेश किया जिसमें कन्या की न्यूनतम विवाह में वृद्धि, अर्न्तजातीय विवाह को मान्यता स्त्रियों को पुरूषों के समान अधिकार, तलाकशुदा स्त्री को पति से भरण-पोषण लेने का अधिकार, विधवा पुर्नविवाह को मान्यता, स्त्री को पुत्री, पत्नी के रूप में पारिवारिक सम्पत्ति का अधिकार, स्त्री को गोद लिये जाने व लेने का अधिकार, अवकाश आदि का प्रावधान था। हालांकि यह बिल संसद में उस समय पारित नहीं हो पाया। इससे दुखी होकर उन्होनें नेहरू मंत्री मंडल से त्यागपत्र दे दिया। बाद में यही बिल टुकड़ों में संसद मे पारित हुआ जिसका लाभ आज सम्पूर्ण महिला वर्ग को मिल रहा है। इसी प्रकार डा. अम्बेडकर श्रमिक कानून के भी पिता माने जाते हैं। श्रमिकों के लिए न्यूनतम श्रमकाल, मजदूरी, संवेतन अवकाश, पुरूष महिला को समान श्रम के लिए समान मजदूरी, प्रसव अवकाश आदि कई मुद्दों पर उन्होंने कानून बनाकर महान कार्य किया। जनसंख्या के पूरी तरह से स्थानांतरण किये जाने पर जोर दिया था। बाबा साहेब का विचार दर्शन भारत को जीवंत व प्राणवान बनाने की संजीवनी है। राष्ट्र इस संजीवनी को आत्मसात करने में जितना अधिक समय लगायेगा उतना ही पीछे रहेगा।

डा. अम्बेडकर की राष्ट्र परिभाषा व्यापक थी। उनका राष्ट्र एक निश्चित कल्याण का भाव था। राष्ट्र के पीड़ित, शोषित, वंचित तथा उपेक्षित वर्ग की सेवा ही उनका राष्ट्र धर्म था। देश की आजादी का जितना महत्व था उतना ही महत्वपूर्ण इस देश को मानसिक गुलामी से मुक्त कराना था। उन्होंने एक ओर समाज में व्याप्त धार्मिक अंधविश्वास, कर्मकांड, पाखंड, जातिवाद व जाति आधारित व्यवस्था की छज्जियां उड़ाई तो दूसरी ओर तथागत बुद्धके प्रज्ञा, शील, दया व करूणा के मार्ग को अपनाया तथा देश को अपनी गौरवशाली संस्कृति की ओर वापस मोड़ा। अपने संघर्ष काल में विरोधियों के द्वारा निरन्तर अपमान व समाज के तिरस्कार वे विद्रोही हो गये थे। लेकिन उनके विद्रोह में गंभीरता थी। वे विद्रोही थे लेकिन विध्वसंक नहीं थे। यह खेद का विषय है कि कभी-कभी डा. अम्बेडकर के विराट व्यक्तिव को विवादस्पद बनाने की कोशिश की जाती है। दरअसल वे जन्म पर आधारित वर्णव्यवस्था के प्रबल विरोधी थे। क्योंकि वे इसे देश, समाज व मानव मात्र के विकास में बंधक मानते थे। वे जानते थे कि इस देश के धर्म व सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाये बिना राजनैतिक आजादी का विशेष महत्व नहीं है।

आज हमारे बीच में बाबा साहेब नहीं है लेकिन उनके विचारों की प्रासंगिकता दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। आज देश की हर ज्वलंत समस्या का समाधान उनके दर्शन में है। देश में आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक व राजनैतिक क्षेत्र में जो विकराल समस्याएं खड़ी है उनके बारे में उन्होंने उस समय ही आगाह कर समाधान के रास्ते सुझा दिये थे। आज कुछ गैरदलित डा. अम्बेडकर को कितना ही कोसे लेकिन जाति व्यवस्था के खात्मे के लिए उनके संघर्ष को दलित कभी नहीं भूलेंगे। कई विद्वान उनके दलित मुक्ति आंदोलन को एक ही वर्ग के कल्याण की बात बताकर उन्हें सम्पूर्ण समाज का नेता नहीं मानते। ऐसे विद्वानों को यह समझना चाहिए कि दलित, आदिवासियों या वंचितों की समस्या पूरे समाज की देन है इसलिए इनके उत्थान की जिम्मेदारी सम्पूर्ण समाज की है। इसलिए सही अर्थो में वे एक राष्ट्रीय नेता थे। जाति व्यवस्था, पाखंड व अंधविश्वास के खिलाफ तो बुद्धभी लड़े और आज वे विश्वव्यापी है। उनका दर्शन सम्पूर्ण मानवता के कल्याण का है। गैरदलित यह क्यों नहीं समझ रहे हैं कि जात-पात इस देश के लिए अभिशाप है जिसके कारण कभी भी एक राष्ट्रीय भाव नहीं पैदा हुआ और बिखरे रहने के कारण छोट-छोटे कबिलाई विदेशियों के आगे भी हारते रहे और गुलाम रहे। जात-पात, भेदभाव, सामाजिक, आर्थिक विषमता व धार्मिक पाखंड के खिलाफ अम्बेडकर मूलतः भारत के भविष्य का दर्शन है।

डॉ. अंबेडकर : कलम का कमाल (भाग:2), संपूर्ण वाड्मय का सार : खंड 12 से साभार

डॉ. अम्बेडकर के साथ दिल को झकझोड़ने वाली छुआछूत की एक घटना

यह घटना 1929 की है। बंबई सरकार ने अछूतों की शिकायतें जानने के लिए एक कमेटी नियुक्त की। मैं भी इस कमेटी का सदस्य था। धुलिया लाईन पर अछूतों का सामाजिक बहिष्कार किया गया था। मैं वहां से पड़ताल करके रेल से चालीस गांव लौट आया। वहां के लोगों ने मुझे रात ठहरने के लिए निवेदन किया। मैं मान गया। चालीस गांव रेलवे स्टेशन से महारवाड़ा लगभग 2 मील के फासले पर था। मुझे एक घंटा प्लेटफार्म पर इंतजार करना पड़ा, तब टांगा आया। मैं और टांगा चालक केवल दोनों ही टांगे में सवार थे। शेष लोग छोटे रास्ते से पैदल चले गए। अभी टांगा 200 कदम ही चला होगा कि उसकी मोटरकार से टक्कर हो सकती थी। एक पुलिसजन के चिल्लाने से दुर्घटना होते-होते बची। मैं हैरान था कि जो टांगा चालक हर रोज ही टांगा चलाता था। इतना नातजुर्बेकार भी हो सकता है।

किसी तरह हम नदी की पुली के पास पहुंचे। पुली के दोनों तरफ पत्थर लगे हुए थे। सड़क से पुली की ओर जाने के लिए तीखे तौर पर घूमना पड़ता था। घोड़ा बिदक गया और टांगे को एक पहिया पत्थरों से इतनी जोर से टकराया कि टांगा पुली से नदी में जा गिरा। मैं भी पुल के पत्थरों पर जा गिरा। मुझसे पहले पहुंचने वाले लोगों ने रोते कुरलाते हुए मुझे उठाया और मराठवाड़ा ले गए। पत्थरों के साथ टकराने से मुझे कई घाव हो गए। मेरी टांग की हड्डी टूट गई। कई दिनों तक मैं चल नहीं सका। मैं समझ नहीं पाया कि ये सब क्यों हुआ। टांगा हर रोज पुली पर से गुजरता है। चालक के होते हुए कभी ऐसा नहीं हुआ।

जांच-पड़ताल करने पर पता चला कि टांगे वाले एक अछूत को टांगे पर नहीं ले जाना चाहते थे। महार भी ये नहीं चाहते थे कि मैं रेलवे स्टेशन से मराठवाड़ा तक पैदल जाऊं। ये उनके स्वाभिमान के खिलाफ था। टांगे वाले से एक समझौता किया गया। वह यह कि टांगे वाला अपना टांगा तो देगा मगर उसको चलाएगा नहीं। महार टांगा ले सकते हैं, चालक किसी और को ले ले। महारों ने अपने में से ही एक को टांगा चालक बना लिया। उन्होंने मेरी सुरक्षा की अपेक्षा अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान ज्यादा रखा। उस समय मुझे यह मालूम हुआ कि एक हिन्दू टांगे वाला, जो मामूली चालक से बेहतर नहीं था, उन तमाम अछूतों से उत्तम व ऊंचा था चाहे उनमें एक अछूत (अंबेडकर) बैरिस्टर-एट-लॉ ही क्यों न था।

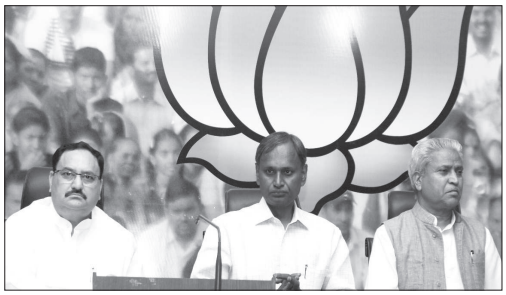

भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय 11, अशोक रोड, दिल्ली पर 14 अप्रैल को भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनायी गयी। इस जयंती के मौके पर लोगों को शुभकामनाएं देते हुए (बायें से) भाजपा महासचिव जे. पी. नड्डा, विशेष आमंत्रित सदस्य, राष्ट्रीय कार्यकारिणी डॉ. महिप सिंह एवं संगठन महासचिव श्री रामलाल जी

सफाई कामगारों का उत्थान सुधारवाद से नहीं बल्कि वैचारिक क्रांति से होगा

विनोद कुमार

साथियों,

तथागत गौतम बुद्ध एवं महात्मा ज्योतिबाराव फुले के सामाजिक कार्यों से प्रेरित व्यवस्था प्रवर्तक, संविधान शिल्पकार, भारत रत्न बाबा साहेब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर के 123वें जन्मदिवस पर आप सभी को मंगल कामनाएं। डॉ0 भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल, 1891 महू (मध्य प्रदेश) में एक दलित परिवार में हुआ था। उस समय की विषमतावादी सामाजिक व्यवस्था के तहत बाबा साहेब को अपने बचपन, अध्ययन एवं संघर्ष के समय में बार-बार अपमानित होना पड़ा। किन्तु अपने दृढ़ निश्चय एवं कठिन संघर्ष से हजारों वर्ष से दबे-कुचले समाज के लिए भारत का संविधान लिखकर सामाजिक समानता, आर्थिक, शैक्षणिक एवं राजनैतिक अधिकार प्राप्त किए। बाबा साहेब दलित उत्थान के लिए एक क्रांतिकारी संदेश में कहा कि हे दलितों! मनुवादी लोगों द्वारा थोपे गए अपने पैतृक पेशे को छोड़कर शिक्षा ग्रहण करो, संघर्ष करो एवं संगठित रहो। दलित समाज की कुछ उपजातियों ने खासकर महारों ने एवं उत्तर भारत में चमारों ने बाबा साहेब के बताए मार्ग पर चलकर उपरोक्त अधिकारों के लिए संघर्ष किया, उन्होंने कुछ हद तक इन सभी अधिकारों को प्राप्त किया।

सफाई पेशे से जुड़ी जातियां जिनको विभिन्न प्रदेशों में भिन्न-भिन्न नामों से जाना जाता है उनमें प्रमुख हैं - बाल्मीकि, मेहतर, डोम, चांडाल, हेला, चूहड़ा, लालबेगी, भंगी, धानूक आदि। इन जातियों में ज्यादातर लोगों का कार्य सरकारी-अर्धसरकारी एवं स्थानीय निकायों आदि में सफाई कामगार के रूप में कार्य करना है। महात्मा गांधी, वीर सावरकर एवं एम.आर. जैकर द्वारा सफाई पेशे से जुड़ी जातियों के बीच में सुधारवादी आंदोलन चलाये गए, लेकिन उनका परिणाम शून्य रहा और इस समाज की स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हो पाया। अब समय आ गया है कि इस पेशे से जुड़े लोगों को अम्बेडकर की विचारधारा को अपनाना ही पड़ेगा और अपने पैतृक पेशे को छोड़कर शिक्षा, संघर्ष और संगठन के रास्ते पर चलना पड़ेगा। तभी इस समाज का विकास संभव है। यहां हम यह बताना जरूरी समझते हैं कि वर्तमान समय में जो व्यक्ति इस पेशे में कार्यरत् है, वे आज संकल्प लें एवं ऐसा सामाजिक माहौल बनाएं कि हम बच्चों को शिक्षित करके इस कार्य में आने से रोकें एवं रोजगार के अन्य अवसर तलाशें ताकि सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें। वैसे भी यह कार्य पूर्ण रूप से ठेकेदारी प्रथा में जा चुका है, जिसमें न पैसा है, न मान-सम्मान है। अतः इस कार्य से निजात पाना ही होगा।

पहले से ही इस पेशे को सम्मान से देखा नहीं गया है और अब इसमें जब से ठेकेदारी प्रथा लागू कर दी गयी है, तब से इस समाज का शोषण और तेज हो गया है और इस पेशे में कार्यरत लोगों का जीवन स्तर दिन ब दिन गिरता जा रहा है। आए दिन सफाई पेशे से जुड़े नेताओं द्वारा इस समाज के विकास के लिए नगर पालिकाओं आदि पर धरने-प्रदर्शन होते रहते हैं, जिसकी वजह से इनको थोड़ी-बहुत सुविधाएं मिल जाती है, लेकिन समाज की सामाजिक, आर्थिक स्थिति जस की तस बनी रहती है। इसलिए हमें परिवर्तन की ओर जाना पड़ेगा और रोजगार के अन्य अवसर तलाशने होगें। तभी जाकर अपना मान-सम्मान हासिल कर सकते हैं।

सफाई पेशे से जुड़े सामाजिक संगठनों एवं इस समाज के बुद्धिजीवियों को आपस में तालमेल बिठाकर वैचारिक आंदोलन के द्वारा इस समाज को भारतीय सामाजिक व्यवस्था में मान-सम्मान सुनिश्चित कराने के लिए वैचारिक क्रांति करनी होगी। यदि इस समाज का बुद्धिजीवी एक हो जाए और वैचारिक आंदोलन शुरू कर दे तो वह दिन दूर नहीं जब यह समाज भी गुलामी से मुक्त हो जाएगा एवं अपना मान-सम्मान एवं अधिकार स्वतः हासिल कर लेगा। जैसे कुछ और दलित जातियों का वैचारिक आंदोलन के द्वारा उत्थान हुआ है। मनुवादी कभी नहीं चाहेंगे कि हम मानसिक गुलामी से मुक्त हों। आज बाबा साहेब की 123वीं जयंती पर हमें संकल्प लेना चाहिए कि मानसिक गुलामी से मुक्ति के लिए ज्योतिबा फूले, शाहूजी महाराज एवं डॉ. अंबेडकर के विचारों पर चलना होगा। यही बाबा साहेब के लिए हमारी असली श्रद्धांजलि होगी।

पाठकों से अपील

'वॉयस ऑफ बुद्धा' के सभी पाठकों से निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक वार्षिक शुल्क/शुल्क जमा नहीं किया है, वे शीघ्र ही बैंक ड्रॉफ्ट द्वारा 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के नाम से टी-22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 को भेजें। शुल्क 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के खाता संख्या 0636000102165381 जो पंजाब नेशनल बैंक की जनपथ ब्रांच में है, सीधे जमा किया जा सकता है। जमा कराने के तुरंत बाद इसकी सूचना ईमेल, दूरभाष या पत्र द्वारा दें। कृपया 'वॉयस ऑफ बुद्धा' के नाम ड्राफ्ट या पैसा न भेजें और मनीआर्डर द्वारा भी शुल्क न भेजें। जिन लोगों के पास 'वॉयस ऑफ बुद्धा' नहीं पहुंच रहा है, वे सदस्यता संख्या सहित लिखें और संबंधित डाकघर से भी सम्पर्क करें। आर्थिक स्थिति दयनीय है, अतः इस आंदोलन को सहयोग देने के लिए खुलकर दान या चंदा दें।

सहयोग राशि:

पांच वर्ष : 600 रुपए

एक वर्ष : 150 रुपए

भाजपा के घोषणापत्र में डाइवर्सिटी

बहुजन बुद्धिजीवियों से एक अपील

एच. एल. दुसाध

इसमें कोई शक नहीं कि दलित-पिछड़े समाज के अनेक मुखर नेताओं के सवर्णवादी भाजपा के साथ जुड़ने से स्वतंत्र बहुजन राजनीति हाशिये पर चली गयी है। ये नेता सत्ता से दूर रहकर भी समय-समय पर जिस तरह बहुजनों के हकों की आवाज बुलंद करते रहते थे, वह दबे-कुचले समाज का मनोबल बढ़ाने में बड़ा सहायक होता था। लेकिन अब बहुजन समाज की वह आवाज छिन चुकी है और एक तरह से भारतीय राजनीति, मंडल पूर्व के दौर में चली गयी है, जब सारे एजेंडे गांधीवाद, मार्क्सवाद व राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े सवर्णवादी दल तय करते थे। तब सम्पदा-संसाधनों में बहुजनों की वाजिब हिस्सेदारी की बात सुनने को ही कोई तैयार नहीं था। किन्तु मंडलोत्तर काल में हालात पूरी तरह बदल गए। बहुजनों में जाति चेतना के उभार ने सवर्णो को राजनीतिक रूप से एक लाचार समूह में तब्दील कर दिया और वे अपना वजूद बचाए रखने के लिए अपने घोषणा-पत्रों में वही बातें शामिल करने लगे जिनकी हिमायत हमारे बहुजन नेता करते थे।

किन्तु इस लोकसभा चुनाव से पूर्व घटित राजनीतिक घटनाक्रम के बाद, अब वे हालात नहीं रहे। अब सारे एजेंडे कांग्रेस, भाजपा और आप जैसी सवर्णवादी पार्टियाँ तय करेंगी और उनमें शामिल हमारे नेता हां में हां मिलाने के लिए बाध्य होंगे। जहाँ तक भाजपा का सवाल है, हमारे बहुजन नायकों के उससे जुड़ने से उसे बहुत लाभ हुआ है। पहले लग रहा था कि नरेंद्र मोदी की सांप्रदायिक व सामाजिक न्याय विरोधी छवि के कारण भाजपा सत्ता से वंचित हो जाएगी। किन्तु अनेक बहुजन राजनीतिज्ञों के उससे जुड़ने के बाद राजनीतिक हालात पूरी तरह उसके पक्ष में हो गए हैं। अब वह अस्पृश्यता से मुक्त हो चुकी है। अब अगली सरकार गठन की सारी अनिश्चितता खत्म हो चुकी है। दावे के साथ कहा जा रहा है कि अगली सरकार मोदी के नेतृत्व में भाजपा गठबंधन की बनेगी।

मित्रों, इस बदले हालात में एक बात का खतरा पैदा हो गया है। वह यह कि कहीं आत्मविश्वास से लबरेज भाजपा 'डाइवर्सिटी' के मुद्दे को तो नहीं भुला देगी, जो वह 2009 से लगातार अपने घोषणापत्र में प्रमुखता से उठाती रही है ?इस लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा केंद्र की सत्ता पर काबिज हो या न हो, लेकिन इतना तय है कि उसे बडी बढ़त हासिल होगी। यह भी तय है कि अगर वह मजबूत होकर उभरेगी तो आगामी विधानसभा चुनावों में उसे अनेक नये राज्यों में अपनी सरकार बनाने का अवसर मिल सकता है। ऐसे में भाजपा से जुड़ने वाले बहुजन नेताओं का यह दायित्व होना चाहिए कि वे पार्टी को इस बात के लिए राजी करें कि वह डाइवर्सिटी के एजेंडे से दूर न भागे और अगर भागती है तो इसका इल्जाम इन बहुजन नेताओं पर ही जायेगा। हम तो यही समझेंगे कि इनके जुड़ने से भाजपा इतनी निश्चिन्त हो गयी कि उसे बहुजनो को रिझाने के लिए डाइवर्सिटी की जरुरत ही नहीं महसूस हुई।

भाजपा ने सबसे पहले लोकसभा चुनाव-2009 में अपने घोषणापत्र में खुलकर डाइवर्सिटी की हिमायत की। उसने हिंदी में जारी 2009 के अपने घोषणापत्र के पृष्ठ 29 पर लिखा है - ''भाजपा सामाजिक न्याय तथा सामाजिक समरसता के प्रति प्रतिबद्ध है। पहचान की राजनीति, जो दलितों अन्य पिछड़े वर्गो और समाज के अन्य वंचित वर्गो को कोई फायदा नहीं पहुंचाती का अनुसरण करने के बजाय, ठोस विकास एवं सशक्तिकरण पर ध्यान केन्द्रित करेगी। हमारे समाज के दलित, पिछड़े एवं वंचित वर्गो के लिए उद्यमशीलता एवं व्यवसाय के अवसरों को इस तरह बढ़ावा दिया जायेगा ताकि भारत की सामाजिक विविधता पर्याप्त रूप से आर्थिक विविधता में प्रतिबिम्बित हो।'' 2009 में भाजपा के घोषणापत्र का उपरोक्त अंश सचमुच क्रांतिकारी था। भूमंडलीकरण के इस दौर में बहुजन बुद्धिजीवियों की सबसे प्रमुख मांग यह रही है कि पार्टियाँ-सरकारें बहुजनों के लिए पारंपरिक आरक्षण (महज सरकारी नौकरियों) से परे हटकर, उद्योग-व्यापार में भागीदार बनाने पर विचार करें। सामाजिक विविधता के आर्थिक विविधता में प्रतिबिम्बिन का मतलब यह हुआ कि समस्त आर्थिक गतिविधियों - सप्लाई, डीलरशिप, ठेकों, ट्रांसपोर्टेशन इत्यादि में जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी भागीदारी। भाजपा ने अपने घोषणापत्र में सामाजिक विविधता को आर्थिक विविधता में प्रतिबिम्बित करने का एलान कर एक क्रांति की ही घोषणा कर दी थी।

उसकी यह घोषणा सिर्फ लोकसभा चुनाव-2009 तक ही सीमित नहीं थी। उसने लगभग वही बातें बिहार विधानसभा चुनाव-2010 में दुहराते हुए कहा -'पहचान की राजनीति के बदले भागीदारी नीति का अनुसरण करते हुए समाज के दलित, पिछड़े, वंचित एवं कमजोर वर्गो के ठोस विकास एवं सशक्तिकरण पर ध्यान केन्द्रित किया जायेगा। समाज के इन वर्गो के लिए उद्यमशीलता और व्यवसाय के अवसरों को बढाया जायेगा।'' भाजपा ने उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनाव-2012 में फिर डाइवर्सिटी-केन्द्रित घोषणापत्र जारी करते हुए सामाजिक विविधता को आर्थिक विविधता में तब्दील करने के अपने इरादे की घोषणा की।

जहाँ तक भाजपा से जुड़ने वाली रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी का सवाल है, उसने भी बिहार विधानसभा चुनाव-2010 में डाइवर्सिटी के पक्ष में बढ़-चढ़कर घोषणा की थी। उस चुनाव में चूँकि उसका घोषणापत्र राजद के साथ संयुक्त रूप से जारी हुआ था इसलिए घोषणापत्र में तो नहीं किन्तु रेडियो और टीवी पर लोजपा को जितनी बार अपनी बात रखने का अवसर मिला, हर बार उसने यह दोहराया कि ''ठेकेदारी, सप्लाई, वितरण, फिल्म, मीडिया आदि धनोपार्जन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। सदियों से व्याप्त आर्थिक और सामाजिक असमानता को खत्म करने के लिए नीतिगत फैसले करने का अधिकार राज्य कार को नहीं है। परन्तु धनोपार्जन के सभी स्रोतों और संसाधनों में सभी वर्गो को डाइवर्सिटी के आधार पर संख्यानुपात में सामान भागीदारी और हिस्सेदारी की जरुरत है, लोजपा इसका समर्थन करती है।''

बहरहाल, भाजपा 2009 से ही लगातार विविधता (डाइवर्सिटी) लागू करने का आश्वासन देती रही है। लोजपा ने भी बिहार में डाइवर्सिटी का समर्थन किया है। चिंता की बात यह है कि जिस तरह दलित-पिछड़े समाज के मुखर नेताओं के भाजपा से जुड़ने के बाद आगामी लोकसभा चुनाव में उसकी जीत पक्की होती दिख रही है, कहीं ऐसा न हो कि वह डाइवर्सिटी की बात भूल जाये। ऐसे में आप सब बहुजन समाज के जागरुक लोगों व बुद्धिजीवियों से हमारी अपील है की यदि आपका भाजपा में शामिल होनेवाले नेताओं से जरा भी संपर्क है तो उन पर दबाव बनायें कि वे यह सुनिश्चित करें कि भाजपा अपने पुराने वादे से भागने न पाये। चूँकि डाइवर्सिटी ही आज बहुजन समाज की असल मांग है इसलिए राजग यदि खुलकर डाइवर्सिटी की बात अपने घोषणापत्र में शामिल करता है तो बहुजन बुद्धिजीवी भाजपा से नए-नए जुड़े बहुजन नेताओं के समर्थन में भी सामने आ सकते हैं। यदि ऐसा नहीं होता है हम इन नेताओं की राह में कांटे बिछाने में हम सर्वशक्ति लगायेंगे।

(अनेक पुस्तकों के लेखक एच.एल दुसाध बहुजन डाइवर्सिटी मिशन, दिल्ली के संस्थापक अध्यक्ष हैं)

(साभार : फारवर्ड प्रेस)

Appeal to the Readers

You will be happy to know that the **Voice of Buddha** will now be published both in Hindi and English so that readers who cannot read in Hindi can make use of the English edition. I appeal to the readers to send their contribution through Bank draft in favour of **'Justice Publications'** at T-22**,** Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001. The contribution amount can also be transferred in 'Justice Publications' Punjab National Bank account no. 0636000102165381 branch Janpath, New Delhi, under intimation to us by email or telephone or by letter. Sometimes, it might happen that you don't receive the Voice of Buddha. In that case kindly write to us and also check up with the post office. As we are facing financial crisis to run it, you all are requested to send the contribution regularly.

Contribution:
Five years : Rs. 600/-
One year : Rs. 150/-

घाटी पर मंडराती वहाबी छाया

आलोक बंसल

जम्मू-कश्मीर राज्य से हाल ही में मिले संकेत काफी अशुभ हैं। सांभा जिले में पुलिस चौकी और सेना अधिकारियों की एक मैस पर आतंकवादी हमला किया गया, जिसमें कई लोगों की जानें गईं। इसके साथ ही आतंकवादियों ने कश्मीर घाटी के केरन सेक्टर में नियंत्रण रेखा पार करके घुसपैठ करने की कोशिश की। यह और अधिक आश्चर्य की बात थी क्योंकि घुसपैठियों ने नियंत्रण रेखा के उस तरफ अपने सुरक्षित ठिकानों की तरफ भागने के बजाए खंदकें खोद कर दो सप्ताह से अधिक समय तक भारतीय सेना से लड़ने का फैसला किया था। इस तरह का प्रयास अभूतपूर्व था। घुसपैठियों द्वारा दिखाए गए इस ढंग के दुस्साहस ने सुरक्षा बलों को चकित कर दिया था और उनके बीच पाकिस्तानी स्पेशल फोर्सेज की मौजूदगी की चर्चा थी, लेकिन उसमें नियमित सेना की मिलीभगत मान भी लें, तो भी, आतंकवादियों द्वारा प्रदर्शित किया गया दुस्साहस खतरनाक था।

इसलिए इस परिवर्तन के कारणों का मूल्यांकन करना आवश्यक है और कश्मीर घाटी के वर्तमान परिदृश्य के विश्लेषण से ये कारण साफ हो जाते हैं। कश्मीर घाटी पर एक सरसरी नजर दौड़ाएं तो हम पाएंगे कि वहाबी मस्जिदों और संस्थाओं की संख्या हाल के समय में बढ़ गई है और इसके परिणामस्वरूप पारंपरिक सूफी इस्लाम, जो कश्मीर घाटी का प्रमुख मजहब था, उस पर, कम से कम जहां तक शहरी युवाओं का संबंध है, कट्टरपंथी सलाफी इस्लाम हावी हो चुका है।

राज्य सरकार के प्रति युवाओं में आम तौर पर मोहभंग की स्थिति, व्यावहारिक स्थानीय शासन तंत्र का अभाव और विभिन्न सलाफी संगठनों को बड़े पैमाने पर बाह्य स्रोतों से प्राप्त हो रहे धन से इसे प्रोत्साहन मिला है। साथ ही साथ पाकिस्तान की घटनाओं को लेकर भी एक व्यापक असंतोष है, जिसके परिणामस्वरूप इस्लामाबाद आदर्श भूमिका में नहीं रह गया है, कुंठित युवा अपनी कल्पनाओं की दुनिया वाले समाधानों के लिए वैश्विक इस्लामी संगठनों के प्रति आकृष्ट हो रहे हैं।

परिणाम यह है कि घाटी के शहरी इलाकों में युवा अब खुद को पाकिस्तान के साथ जोड़कर नहीं देखते हैं, बल्कि एक काल्पनिक वैश्विक इस्लामी अमीरात की दिशा में समाधान खोज रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप स्वाभाविक तौर पर ही वैश्विक इस्लामी संगठन के साथ उनका सहयोग बढ़ा है और इस बढ़ी हुई प्रेरणा का नतीजा कश्मीर में हाल के दिनों में स्थानीय आतंकवादियों की वृद्धि में दिखा है। समाज में बढ़ती असहिष्णुता का भी कारण यही है, जिसके तहत महिलाओं की स्वतंत्रता पर आपत्तियां की जा रही हैं, जो पारंपरिक रूप से कश्मीरी समाज का आधार स्तम्भ रही हैं। बुर्कों और दाढ़ियों की बढ़ती संख्या साफ देखी जा सकती है। कश्मीर के महिला बैंड को बंद होने के लिए मजबूर किया गया था और महिलाओं को कैसी पोशाक पहननी चाहिए, इस पर फतवे लगाए जा रहे हैं।

इस सबके साथ ही, अल्पसंख्यकों के प्रति असहिष्णुता बढ़ रही है। घाटी भर में कई ईसाई स्कूलों, चर्चों और संस्थानों पर हमले हुए हैं। कश्मीरियों को कथित तौर पर ईसाइयत की ओर प्रेरित करने के लिए एक ईसाई पादरी को गिरफ्तार किया गया था। इस तरह की घटनाओं की जांच से संकेत मिलता है कि कई हमलों को वहाबी प्रभाव वाले संगठनों द्वारा उकसाया गया था। कश्मीर की शरीया अदालत ने जनवरी 2012 में ईसाई स्कूलों के खिलाफ एक फतवा जारी किया था और जम्मू-कश्मीर सरकार से उनका प्रबंधन अपने हाथों में लेने के लिए कहा था। चूंकि ईसाई स्कूल लोकप्रिय हैं और वहाबियों द्वारा प्रचारित की जा रही कट्टरपंथी विचारधारा के प्रसार में एक प्रमुख बाधा माने जाते हैं, इसलिए उन्हें विशेष रूप से निशाना बनाया जा रहा है। इसके अलावा, वैश्विक इस्लामी संगठनों के साथ बढ़ती निकटता ईसाइयों को पसंदीदा निशाना बनाती है। इसके परिणामस्वरूप 2013 में घाटी में रहने वाले विदेशियों पर मतान्तरण का आरोप लगाते हुए हमले किए गए थे।

लेकिन वहाबी हमलों के सबसे बड़े शिकार कश्मीर घाटी के शिया अल्पसंख्यक हुए हैं, जो डोगरा और सिख शासन के अधीन सदियों से घाटी में सुन्नियों के साथ शांति से रहते रहे आए हैं। यहां तक कि स्वतंत्रता और कश्मीर के भारत में विलय के बाद भी शियाओं को निशाना बनाने की कोई घटना नहीं घटी थी। लेकिन दुनिया भर में इस्लामी समाज के बीच बढ़ रहे वहाबी पंथ के चलन ने शियाओं के शांतिपूर्ण अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है। नफरत की जो विचारधारा इराक या सीरिया में शियाओं के खिलाफ हिंसा को जायज ठहराती है, वही विचारधारा घाटी से भी शियाओं का सफाया करने की वजह बनती जा रही है। विभिन्न मजहबी जमातों द्वारा बांटा जा रही नफरत का साहित्य शियाओं को ईमान से भटके हुए लोगों के तौर पर पेश करता है और बहुसंख्यक समुदाय को उनके खिलाफ हिंसा में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसमें से कुछ साहित्य तो शियाओं को कश्मीर घाटी से खदेड़ने की भी वकालत करता है। 12 लाख से अधिक की संख्या वाला शिया समुदाय लद्दाख के करगिल क्षेत्र और कश्मीर घाटी के कुछ भागों में बहुसंख्यक भी है, और राज्य के सभी तीन भागों-जम्मू, कश्मीर और लद्दाख में रहता है। हालांकि उन पर अत्याचार केवल कश्मीर घाटी में हो रहा है। अच्छी-खासी आबादी होने के बावजूद कश्मीर में शिया समुदाय को मुहर्रम के दौरान जुलूस निकालने की अनुमति नहीं मिलती है, और इस तरह जम्मू-कश्मीर देश का एकमात्र ऐसा राज्य है, जहां मुहर्रम के जुलूस की अनुमति नहीं होती है। इस्लाम के फिरकों के बीच हिंसा, जो पाकिस्तान में स्थायी बीमारी बन कर फैल चुकी है, नियंत्रण रेखा के पार कश्मीर घाटी में भी घुस चुकी है और बडगाम जिले में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी है, जहां जुलाई 2013 में सांप्रदायिक संघर्ष में एक दर्जन से अधिक घरों को जला दिया गया था। स्थिति केवल सेना तैनात करने के बाद नियंत्रित की जा सकी, क्योंकि शिया समुदाय स्थानीय प्रशासन को पूर्वाग्रहग्रस्त मानता था।

बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर द्वारा दिया हुआ विचार 'थॉउट्स ऑन पाकिस्तान' एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। क्या हम अंबेडकरवादी उस परंपरा को आगे बढ़ा पा रहे हैं? अपने अधिकारों के लिए सोचते और संघर्ष करते हैं और करना भी चाहिए लेकिन हमें विदेश नीति, देश की सीमा और सुरक्षा के बारे में भी चिंतन करना चाहिए। अतीत में हम भी यह कार्य नहीं कर सके लेकिन अब करेंगे।

न केवल शिया बल्कि बेहद छोटा सा, शांतिपूर्ण और अहिंसक अहमदिया समुदाय भी घाटी में डरा-सहमा रहता है। कश्मीर के बड़े मुफ्ती ने मई 2012 में राज्य विधानसभा को पाकिस्तान की तर्ज पर अहमदिया समुदाय को गैर-मुसलमान घोषित करने का विधेयक पास करने के लिए कहा। इसी प्रकार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) के बाल्टिस्तान के एक इस्लामी फिरके नूरबख्शी को, जिसके अनुयायी तुर्तुक क्षेत्र और कारगिल के कुछ हिस्सों में हैं, वहाबी मतान्तरणकर्ताओं द्वारा धमकी दी जा रही है। वहाबी और सुन्नी मौलवी नूरबख्शी युवाओं को वहाबी और सुन्नी मत में मतान्तरित कर रहे हैं। दुर्भाग्यवश, इस बेहद छोटे से संप्रदाय के पास अपने अनुयायियों को यह सिखाने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा नहीं है कि उनके मत के मूल सिद्धांत क्या हैं। इसके परिणामस्वरूप नूरबख्शी युवा हज सहित किसी भी कारण से जब इलाके से बाहर निकलते हैं, तब वे दूसरे फिरकों के मतान्तरण कराने वालों के हाथों आसानी से शिकार हो जाते हैं।

पाकिस्तान समर्थक अलगाववादी, जो घाटी में स्थानीय समर्थन खो चुके हैं, अब उग्रवाद को जम्मू और लद्दाख ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका विशेष ध्यान जम्मू क्षेत्र में पुंछ, राजौरी और डोडा तथा लद्दाख में कारगिल पर रहा है। जम्मू क्षेत्र में उन्हें ग्राम सुरक्षा समितियों द्वारा चुनौती दी गई है, जिनमें मुख्य रूप से पूर्व-सैनिक शामिल हैं। ये समितियां लंबे समय से अलगाववादियों की आंख का कांटा बनी हुई हैं, जिसकी वजह से ही वे जम्मू क्षेत्र में सांप्रदायिक दंगे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। वे इसकी आड़ में इन समितियों को शस्त्रहीन कराने की कोशिश कर रहे हैं। अलगाववादियों का यह भी मानना है कि धार्मिक पर्यटन भी उनके अलगाववादी एजेंडे के लिए एक बाधा है, जिसके तहत भारत भर से लाखों तीर्थयात्री जम्मू और कश्मीर में विभिन्न धार्मिक स्थलों की यात्रा करते हैं। वे इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शनों का आयोजन करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि वे इन तीर्थयात्रियों के खिलाफ आम जनता में नकारात्मक भावनाएं पैदा करने में सफल नहीं रहे हैं, क्योंकि इन तीर्थयात्राओं से रोजगार पैदा होता है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिलता है।

अलगाववादियों को हाशिए पर लाने के लिए यह आवश्यक है कि सभी मजहबी और सांप्रदायिक अल्पसंख्यकों को हर हाल में पूरी सुरक्षा प्रदान की जाए। हालांकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कश्मीर पर बहस पहले ही घाटी से स्थानांतरित होकर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पहुंच चुकी है, लेकिन जम्मू और कश्मीर में लोगों को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की घटनाओं के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है।

आवश्यकता इस बात की है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की जानकारियां देने और साथ ही व्यापक इस्लामी दुनिया में घटनाओं से परिचित कराने के लिए सेमिनार आयोजित किए जाएं, ताकि आम जनता कट्टरपंथ के खतरों को समझ सके। कश्मीर घाटी तक एक रेलवे लिंक की स्थापना और मुगल रोड को खोलने से राज्य के शेष भारत के साथ एकीकरण में वृद्धि होगी। हालांकि इन मार्गों के साथ नए शहरों को विकसित करने की आवश्यकता है। इनमें से कुछ शहरों का उपयोग विस्थापित कश्मीरी पंडितों का घाटी में पुनर्वास करने में किया जा सकता है। इसी प्रकार दूरदराज के गांवों तक पर्यटन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि पर्यटन के लाभ राज्य के सभी कोनों तक पहुंचें और सिर्फ श्रीनगर तक ही सीमित न रह सकें।

इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है कि अमरीकी और नाटो सेनाएं 2014 में अफगानिस्तान से निकल जाएंगी और अगर तालिबान की जीत हुई, तो वैश्विक इस्लामिक अमीरात के अधिकांश जमीनी सिपाही लड़ाई के इस नए मोर्चे की ओर आ जाएंगे, जिसमें कश्मीर शामिल होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि इस राज्य में सुरक्षा के परिवेश को मजबूत किया जाए और राष्ट्रवादी तत्वों को पूरी सुरक्षा दी जाए।

(लेखक सेंटर फार लैंड वारफेयर स्टडीज, नई दिल्ली में वरिष्ठ फेलो हैं।)

(साभार : पांचजन्य)

Diversity in BJP maifesto

An appeal to Bahujan intellectuals

H. L. Dusadh

With many vocal Dalit-OBC leader joining the pro-caste Hindu BJP, there is little doubt that independent Bahujan politics has been relegated to the margins. These leaders, even when not in power, had raised their voice in favour of the rights of Bahujans and thus boosted the morale of the oppressed and repressed communities. The Bahujan community has now lost these voices, and in a sense, Indian politics is back in the era when pro-caste Hindu political parties associated with Gandhism, Marxism and nationalist ideologies set the agenda and when no one paid any heed to the demands of Bahujans for their due share in the resources and assets of the nation.

In the post-Mandal era, the caste Hindus appeared helpless faced with the rise of caste consciousness among the Bahujans and to protect their existence, they started including, in their manifestoes, the same points that were raised by our Bahujan leaders.

But the political churning on the eve of the General Elections has changed the scenario. Now, once again, pro-caste Hindu political parties such as the Congress, the BJP and the AAP will decide the agenda and our Bahujan leaders in these parties will have no option but to quietly acquiesce. As far as the BJP is concerned, it has gained much by our Bahujan heroes associating with it. It is no longer politically untouchable. Initially, it seemed that the BJP will not be able to come to power owing to the communal and anti-social-justice image of Narendra Modi. But with many Bahujan leaders joining it, things have become very favourable for the party. Now, there is no uncertainty as to which party will form the next government. We can say with full confidence that the next government will be of the BJP alliance and that Modi will be its leader.

Friends, this changed scenario brings with it a danger. And that is that the BJP, bubbling with confidence, may do away with "diversity" from its manifesto, where it has had pride of place since 2009. Even if the BJP does not win power after the next General Elections, its strength is set to grow considerably. And that will help it form governments in many new states after the Assembly elections due this year and the next. Against this backdrop, it is the responsibility of the Bahujan leaders who have joined the BJP to persuade the party not to abandon its commitment to diversity. If that happens, the blame will squarely be on the shoulders of these Bahujan leaders. We will conclude that their presence in the BJP has made the party so complacent that it no longer found it necessary to talk about diversity for drawing Bahujan votes.

It was in its manifesto for the 2009 General Elections that the BJP had, for the first time, advocated diversity. The Hindi version of the manifesto says, "The BJP is committed to social justice and social harmony. Instead of practising the politics of identity, which is not helping the Dalits, OBCs and other deprived sections of society in any way, the BJP will focus on their real development and empowerment. Opportunities in entrepreneurship and business for the Dalits, OBCs and deprived sections of society will be provided in such a manner that India's social diversity is reflected in its economic diversity, too." (Page 29)

This excerpt from the BJP's 2009 manifesto is truly revolutionary. In this age of globalisation, one of the key demands of Bahujan intellectuals has been that the parties should think beyond traditional reservations (in government jobs) as far as betterment of Bahujans is concerned and try to make them partners in industry and commerce. 'Social diversity in economic diversity' means that in all economic activities – supply, dealerships, contracts, transport, etc – the share of each community will reflect its size. The BJP's announcement that it would endeavour to bring social diversity in the economy had heralded a revolution.

This announcement was not limited to merely the 2009 General Elections. In the 2010 Bihar Assembly elections too, the same assurance was repeated. "Instead of politics of identity, participatory policy will be followed and the focus will be on real development and empowerment of Dalits, OBCs and weaker sections. More opportunities will be created for these communities in the fields of entrepreneurship and business." In the Uttar Pradesh Assembly polls of 2012, the party again issued a diversity-centric manifesto and announced its intention of converting social diversity into economic diversity.

Ram Vilas 'Paswan's Lok Janashakti party had also committed itself to a plan for diversity in the 2010 Bihar polls. Since, in those elections, the LJP had issued a manifesto jointly with the RJD, it could not say as much as it wanted to. But on TV and radio, whenever the LJP got an opportunity, it repeated that "contractorship, supply, distribution, films, media, etc, had become important sources of income. The state government is not empowered to take policy decisions to end economic inequality. But the LJP supports the formulation that on the basis of diversity, all social groups are entitled to a share in all sources of income and resources in proportion to their population".

In short, the BJP has been promising to implement 'diversity' since 2009. The LJP had also supported diversity in Bihar. As more and more vocal Dalit-OBC leaders are joining the BJP, the chances of its victory in the polls are improving. But what is a cause of worry is that the BJP may forget about diversity once it comes to power. Given the situation, we appeal to all intellectuals and politically aware members of Bahujan communities that, if they even have a nodding acquaintance with the Bahujan leaders who have joined the BJP, they should bring pressure to bear upon the leaders to ensure that the party does not back out of its promises on diversity. Diversity is the key demand of the Bahujan community today. Therefore, if the NDA includes the issue of diversity in its manifesto then the Bahujan intellectuals should support the Bahujan leaders who have joined the BJP. Otherwise, they should do everything possible to sow thorns in the way of these leaders.

(A author of many books, HL Dusadh is the founding member of Bahujan Diversity Mission, Delhi.)

(Courtesy : Forward Press)

बाबा तेरी जय हो

हे दलितों के भीम महान!
तेरी जय हो, जय–जय–जय हो।
तेरी जय हो जय हो जय हो।
तेरी जय–जय, जय–जय–जय हो।।
हे दलितों के भीम महान!
थी अंधकार की खाई,
होती थी नित्य लुटाई।

होती थी रोज पिटाई,
दलितों को राह बताई।
तेरी जय–जय, जय–जय–जय हो।।
हे दलितों के भीम महान!
तुने गिरता दलित उठाया,
भारत संविधान बनाया।
दलितों का हक दिलाया,
गिरजन मानवता पाया।

तेरी जय–जय,
जय–जय–जय हो।।
हे दलितों के भीम महान!

–टी. एस. सुमन

VOICE OF BUDDHA

Publisher : Dr. UDIT RAJ (RAM RAJ), Chairman - Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42

● Year : 17 ● Issue 11 ● Fortnightly ● Bi-lingual ● 16 to 30 April, 2014

Undeclared Communalism

Dr. Udit Raj

Bhartiya Janata Party is often accused of communal politics. The so-called progressive writers, thinkers and politicians have created an impression as if BJP is actually a communal party by repeatedly raising the bogey of communalism against it. AAP leader, Shazia Ilmi's statement that Muslims should also become communal, has made this issue further debatable. Most of the members of the Muslim community are made to cast their votes on communal lines. Not only the Muslim leaders but some Hindu leaders also ensure that somehow BJP is defeated. Since 1952, this has been the pattern of electoral politics. Elections are the forum for raising people's issues but this awareness has not been created among Muslims by their leaders. Various parties play the communal card to the hilt to seek the votes of Muslims rather than raising the issue of their development.

People who are active among Muslims are fully aware of this mind-set of the community. Mind-set of people of any caste or community is moulded by leaders and intellectuals of that particular caste or community. The Leftists are all the time harping that communalism is the biggest problem facing the country and by taking this stand, they have made both gains and losses. Wherever they could not emerge as an alternative to BJP, they could hardly garner Muslim votes and lost their base. In Uttar Pradesh and Bihar, when the Leftists had emerged as an alternative to Samajwadi Party, BSP, RJD, JDU and sometimes even the Congress Party and BJP, the Muslims rejected the Leftists and they lost their base. The Leftists continued to get the benefit of their stand on communalism in West Bengal and Kerala because they emerged as an alternative there. Can tbe Leftists be called as well wishers of Muslims? Have they not misled the Muslims by diverting their attention from the issues of development and share in governance. I have myself made sincere efforts for raising the issues faced by Muslims but during elections, their mind-set works only in the direction of defeating BJP. Communalism has been the biggest bane of Indian politics which has caused more harm than casteism.

It is unfortunate that the so-called intellectuals and secularists are not ready to understand this reality. It is because of this reason that the youth and the middle class keep distance from them and are now joining Bhartiya Janata Party and it is now an open secret that it has taken the shape of a huge caravan. It is this group of people which is playing a stellar role in creating a suitable atmosphere for making Narendra Bhai as the next Prime Minister ofIndia. The intellectual acumen of these so-called intellectuals and secularists is also dubious as they are never tired of branding RSS and BJP as fascists. Their knowledge of history and society is shallow. The Indian society cannot be compared with any other society. The other societies are not fragmented into thousands of castes. If Fascism came to Germany, it was so because the society was united there whereas our society is not only divided into castes but gotras and sub gotras and even beyond that. We cannot bring about Fascism in our society even if we want to do so. The Congress Party imposed Emergency during 1975-77 but it failed. To create a unified society, there will be a need for a cultural revolution in which the State has to play a significant role. We can give the example ofChina in this regard but there the circumstances were different. The caste system was prevalent in Japan also but it was abolished. InIndia, it does not seem possible to abolish caste system. Baba Saheb Dr. B.R. Ambedkar launched a struggle for establishing a casteless society but he could not achieve his goal. The RSS is a powerful organization and, if they so desire, they can help in establishing a casteless society in the country. People who raise the bogey of Fascism against RSS and BJP either lack intellectual acumen or they are doing so for selfish interests.

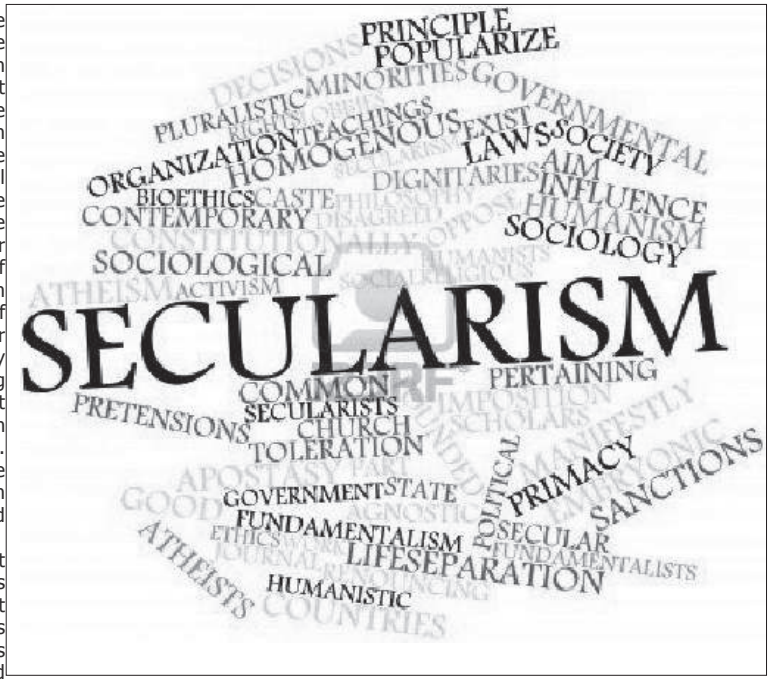

Till 1990, Congress Party has been ruling Uttar Pradesh without much of opposition and during that period, Hindu-Muslim riots took place. Not a single year passed without curfew being imposed in cities for several days because of riots. The Congress Party owes it to the people to explain as to why the communal riots were an exception in Uttar Pradesh after the Congress Party went out of power. The 1984 Sikh riots were much larger than the Gujarat riots which took place after the Godhra tragedy. Were thousands of Hindus not killed in Punjab? There is lack of honesty and objectivity in these matters. Because of the bogey of communalism raised by the so-called intellectuals and secularists, it has become a mind-set of the Muslims to defeat BJP. People who are indulging in such activities, they consider BJP a Hindu-dominated party and are doing their best to brand it as communal.

Most of the members of the Muslim community vote against BJP and on this issue Aam Admi Party has said that Muslims should also become communal. I simply laugh at this stand of the Aam Admi Party because Muslims are already doing this. The Aam Admi Party should have appealed to Muslims that instead of following the "Defeat BJP" policy, they should vote for the party which works for their development and provides them security. Thus, these so-called intellectuals and secularists are themselves communal and casteist. Ashish Nandy, the Social Scientist, had said last year that no Dalit or Backward leader had emerged in West Bengal during the last 100 years. Leadership of most of the Left parties is in the hands of upper caste people and this is the reason why their hold is dwindling in North and other places. Shazia Ilmi should, in fact, have said that instead of defeating BJP, Muslims should vote for their development and share in governance.

Publisher, Printer and Editor - Dr. UDIT RAJ (FORMERLY KNOWN AS RAM RAJ), on behalf of Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42, Telefax:23354843, Printed at Sanjay Printing Works, WZ-4A, Basai Road, New Delhi.
Website : www.uditraj.com E-mail: dr.uditraj@gmail.com Computer typesetting by N. K. Karn